

GLOBALISATION AND ENVIRONMENT

IMPORTANT TOPICS AND QUESTIONS

Hindi & English both

3rd video of the series

What are alternatives technologies

Alternative technologies are those technologies that can be used in place of conventional technologies. They are typically more environmentally friendly, sustainable, and economically beneficial. Some key alternative technologies include:

Solar Energy - Technology to generate electricity from sunlight.

Wind Energy - Technology to produce electricity from wind.

Biomass Energy - Energy production from organic materials.

Geothermal Energy - Energy production from the Earth's internal heat.

वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां वे तकनीकें हैं जो पारंपरिक प्रौद्योगिकियों के स्थान पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये आमतौर पर अधिक पर्यावरण-संवेदनशील, टिकाऊ और आर्थिक रूप से लाभदायक होती हैं। कुछ प्रमुख वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों में शामिल हैं:

सौर ऊर्जा - सूरज की रोशनी से बिजली उत्पन्न करने की तकनीक।

विंड ऊर्जा - हवा से बिजली उत्पादन की तकनीक।

बायोमास ऊर्जा - जैविक सामग्री से ऊर्जा उत्पादन।

भूतापीय ऊर्जा - पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से ऊर्जा उत्पादन।

Challenges faced by alternative technologies:

High Initial Costs: Alternative technologies often require significant upfront investment compared to conventional technologies.

प्रारंभिक लागत अधिक होना: वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के लिए अक्सर पारंपरिक प्रौद्योगिकियों की तुलना में प्रारंभिक निवेश में अधिक खर्च करने की आवश्यकता होती है।

Infrastructure Compatibility: Integrating alternative technologies into existing infrastructure can be challenging due to compatibility issues and retrofitting requirements

ढांचा संगठन योग्यता: मौजूदा ढांचे में वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना योग्यता समस्याओं और अनुप्रयुक्तता की मुद्दों के कारण कठिन हो सकता है।

Intermittent Energy Supply: Sources like solar and wind energy can fluctuate based on weather conditions and time of day, posing challenges for consistent energy supply.

अस्थायी ऊर्जा आपूर्ति: सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों की आपूर्ति मौसम की स्थितियों और दिन के समय के अनुसार बदलती रहती है, जिससे नियमित ऊर्जा आपूर्ति में चुनौतियां आ सकती हैं।

How Government is Encouraging the Use of Alternative Technologies?

Financial Incentives: Governments offer subsidies, tax credits, grants, and low-interest loans to reduce the initial costs of adopting alternative technologies

वित्तीय प्रोत्साहन: सरकारें वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के लागू होने की प्रारंभिक लागत को कम करने के लिए सब्सिडी, कर शुल्क छूट, अनुदान और कम ब्याज वाले ऋण प्रदान करती हैं।

Infrastructure Development: Governments facilitate the development of infrastructure such as smart grids and charging stations for electric vehicles.

ढांचा विकास: सरकारें स्मार्ट ग्रिड्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन्स जैसे ढांचों के विकास को सुविधाजनक बनाती हैं।

Public Awareness and Education: Governments promote awareness campaigns and educational programs to inform citizens about the benefits and potential of alternative technologies.

जन जागरूकता और शिक्षा: सरकारें लोगों को वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के लाभ और संभावनाओं के बारे में सूचित करने के लिए जागरूकता अभियान और शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती हैं।

Regulatory Support: Governments establish supportive policies, regulations, and standards to streamline the integration of alternative technologies into the energy sector.

नियामक समर्थन: सरकारें ऊर्जा क्षेत्र में वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के सम्मिलन को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्थक नीतियों, विनियमक और मानक स्थापित करती हैं।

Write down the role of Indian judiciary for protecting environment. Mention two important landmark cases also.

The Indian judiciary plays a crucial role in protecting the environment through interpretation and enforcement of environmental laws, ensuring sustainable development, and safeguarding natural resources. Here are key aspects of its role:

भारतीय न्यायपालिका पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है विधान के व्याख्यान और कानूनों के पालन के माध्यम से, सुनिश्चित करती है कि सतत विकास होता है और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाती है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में शामिल हैं:

Interpreting Environmental Laws

The Indian judiciary plays a pivotal role in interpreting and enforcing environmental laws. Courts have often read expansive meanings into existing legislations to address environmental issues effectively.

भारतीय न्यायपालिका पर्यावरण कानूनों की व्याख्या और प्रवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायालयों ने अक्सर मौजूदा विधानों में विस्तृत अर्थ को पढ़ा है ताकि पर्यावरणीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके।

Public Interest Litigation (PIL)

The judiciary has been instrumental in allowing Public Interest Litigations (PILs) for environmental protection. This has enabled concerned citizens and organizations to approach the courts directly in case of environmental harm.

न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जनहित याचिकाओं (पीआईएल) को अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे चिंतित नागरिकों और संगठनों को पर्यावरणीय क्षति के मामले में सीधे न्यायालयों का रुख करने की अनुमति मिली है।

Establishing Environmental Principles

The judiciary has formulated and enforced key environmental principles such as the Polluter Pays Principle, Precautionary Principle, and Public Trust Doctrine.

न्यायपालिका ने प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, एहतियाती सिद्धांत और सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत जैसे प्रमुख पर्यावरणीय सिद्धांतों को तैयार और लागू किया है।

Landmark Cases

MC Mehta vs. Union of India (1986) - Ganga Pollution Case

This case highlighted the severe pollution in the Ganga River. The Supreme Court directed industries to set up treatment plants and ensured the closure of those not adhering to the guidelines.

इस मामले ने गंगा नदी में गंभीर प्रदूषण को उजागर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योगों को उपचार संयंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया और उन उद्योगों को बंद करने को सुनिश्चित किया जो दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे।

Vellore Citizens Welfare Forum vs. Union of India (1996)

The Supreme Court recognized the Precautionary Principle and Polluter Pays Principle in this case. It dealt with the pollution caused by tanneries in Tamil Nadu and mandated strict adherence to environmental norms.

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को मान्यता दी। यह मामला तमिलनाडु में टैनरी के कारण होने वाले प्रदूषण से संबंधित था और पर्यावरण मानदंडों के सख्त पालन की आवश्यकता बताई।

Scholarly Minds